मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 12 मार्च 2022

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खंड विषयवस्तु पृष्ठ

खंड	विषयवस्तु	पृष्ठ
I.	विनियमन	1
II.	भुगतान और निपटान प्रणाली	2
III.	मुद्रा प्रबंधन	2
IV.	वित्तीय स्थिरता	2
V.	पर्यवेक्षण	2
VI.	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	2
VII.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	3
VIII.	आरबीआई प्रकाशन	3
IX.	जारी आंकड़े	4
X.	आरबीआई बुलेटिन	4
XI	मौद्रिक नीति	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

एकीकृत लोकपाल योजना 2021

रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना 2021 (आरबी-आईओएस) के बारे में सोशल मीडिया के कुछ वर्गों के माध्यम से गलत सूचना फैलाने के मामले आरबीआई के संज्ञान में आए हैं। जनता के बीच बड़े पैमाने पर यह संदेश फैलाया जा रहा है कि वे बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध किए जाने वाले शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए प्रभार/शुल्क देकर या अन्यथा तृतीय पार्टियों के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करवाएँ।

रिज़र्व बैंक ने 9 मार्च 2022 को स्पष्ट किया कि बैंक ने विनियमित संस्थाओं (आरई) के विरुद्ध किए गए शिकायतों के निपटान के लिए किसी भी संस्था के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। बैंक ने आरबी-आईओएस के तहत एक निःशुल्क शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है जिसमें किसी भी रूप में या तरीके से कोई शुल्क या प्रभार का भुगतान शामिल नहीं है। जिन ग्राहकों को सेवाओं में कमी के लिए आरई के विरुद्ध शिकायतें हैं, जिन्हें आरई द्वारा संतोषजनक ढंग से या समय पर सुलझाया नहीं गया है, वे सीधे शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल (https://cms.rbi.org.in)पर या crpc@rbi.org.in पर ई-मेल द्वारा या भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़- 160017 में स्थापित 'केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रोसेसिंग केंद्र' (सीआरपीसी) में प्रत्यक्ष रूप से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों का विनियमन

रिज़र्व बैंक ने 8 मार्च, 2022 को संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 12 के प्रावधानों की समीक्षा की। तदनुसार, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को (i) उनके उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने परिचालन क्षेत्र में व्यक्तियों को शेयर जारी करके, और (ii) मौजूदा सदस्यों को अतिरिक्त शेयर जारी करके शेयर पूंजी जुटाने की अनुमति है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मास्टर निदेश/ परिपत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के महीने में निम्नलिखित मास्टर परिपत्र और मास्टर निदेश जारी किए:

क्रम सं.	विवरण	जारी करने की तारीख
1)	पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार	8 मार्च 2022
2)	भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्मवित्त ऋणों के लिए विनियामकीय ढांचा) निदेश, 2022	14 मार्च 2022
3)	वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन	23 मार्च 2022
4)	वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2021 - संशोधन	31 मार्च 2022
5)	योग्य वित्तीय संविदाओं का द्विपक्षीय निवल राशि निर्धारण	31 मार्च 2022

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने 24 मार्च 2022 को बेंगलुरु में रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) का उद्घाटन किया। रिज़र्व बैंक ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में आरबीआईएच की स्थापना की है।

हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष श्री सेनापति (क्रिस) गोपालकृष्णन हैं तथा उद्योग और अकादमिक जगत के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य हैं। आरबीआईएच का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जो देश में अल्प आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। यह आरबीआईएच की स्थापना के उद्देश्य, अर्थात् वित्तीय समावेशन के अंतर्निहित विषय के साथ भारत में वित्तीय क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवोन्मेष लाना, के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डिजिटल भुगतान (DigiSaathi)

डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का समाधान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 8 मार्च 2022 को दो प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया, जिसका नाम है,

(1) UPI123Pay - फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) भुगतान करने का विकल्प, और

(2) DigiSaathi - एक 24x7 हेल्पलाइन।

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने इन दो पहलों की शुरूआत करते हुए इन पहलों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि रिज़र्व बैंक देश में डिजिटल नवाचारों के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भुगतान प्रणाली की जियो-टैगिंग

रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को गहन बनाने और देश के सभी नागरिकों को समावेशी एक्सेस प्रदान करने के लिए 25 मार्च 2022 को भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग की रूपरेखा जारी की। भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स की जियो-टैगिंग से प्वाइंट्स ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों, क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड आदि जैसे भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की उपलब्धता की उचित निगरानी की जा सकेगी और इस तरह की निगरानी भुगतान अवसंरचना के वितरण को इष्टतम बनाने के लिए नीतिगत मध्यक्षेप का समर्थन करेगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2022 को भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसंगत बनाकर विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. मुद्रा प्रबंधन

अध्ययन एवं विकास केंद्र

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने 28 मार्च 2022 को मैसूर में भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल), रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, के अध्ययन एवं विकास केंद्र (एलडीसी) की स्थापना के लिए शिलान्यास किया। अपने संबोधन में गवर्नर ने ऐसे केंद्र की स्थापना के महत्व पर प्रकाश डाला जो देश के मुद्रा निर्माण पारिस्थिकी तंत्र में मानव संसाधन क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा और उत्कृष्टता के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वर्णिका स्याही निर्माण इकाई

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने 28 मार्च 2022 को मैसूर में बीआरबीएनएमपीएल की वर्णिका स्याही निर्माण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया। गवर्नर ने अपने संबोधन में, भारत में बैंकनोट उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में की गई पर्याप्त प्रगति की सराहना की। उन्होंने जनता, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी; अनुसंधान और विकास एवं नवोन्मेष के संदर्भ में निकट भविष्य में बैंकनोट निर्माण में शत-प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया। यह बैंक नोटों की छपाई में उपयोग किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण और प्रमुख कच्चे माल का निर्माण के लिए पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारत के अभियान के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय स्थिरता

एनएबीएफ़आईडी- अखिल भारतीय वित्तीय संस्था

रिज़र्व बैंक ने 9 मार्च 2022 को घोषणा की कि भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहायता के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) को एक वित्तीय विकास संस्था (डीएफआई) के रूप में स्थापित किया गया है। एनएबीएफआईडी को, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा एआईएफआई के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. पर्यवेक्षण

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च 2022 को, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निदेश दिया है। उक्त बैंक को अपने आईटी सिस्टम की व्यापक सिस्टम लेखा परीक्षा करने के लिए एक आईटी लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करने का भी निदेश दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

BE(A)WARE – एक पुस्तिका

रिज़र्व बैंक ने 7 मार्च 2022 को धोखाधड़ी करने वालों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आम कार्य-प्रणाली और विभिन्न वित्तीय लेन-देन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर "BE(A)WARE" नामक एक पुस्तिका जारी की है। पुस्तिका का उद्देश्य डिजिटल भुगतान करते समय किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ)

कार्यनीतिगत धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुक़ाबला करने (सीएफटी) में आनेवाली कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों की पहचान और निवारण के लिए चल रहे अविरत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में एफएटीएफ प्लेनरी ने कार्यनीतिगत एएमएल/सीएफटी कमियों का सामना कर रहे क्षेत्राधिकारों के संबंध में 'कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिमवाले क्षेत्राधिकार' और 'बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार' शीर्षक से दस्तावेज जारी किया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी 4 मार्च 2022 को एफएटीएफ द्वारा जारी अद्यतित सार्वजनिक विवरण और दस्तावेज में उपलब्ध है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

श्रीलंका और गयाना को ऋण व्यवस्था

रिज़र्व बैंक ने 9 मार्च 2022 को सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को निदेश जारी किया कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने भारत से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्तपोषण हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु दि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ श्रीलंका की सरकार के साथ को करार किया है। एक्ज़िम बैंक ने गयाना के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले जन-समुदाय के लिए 30,000 घरेलू सौर-ऊर्जा प्रकाश प्रणालियों की खरीद एवं संस्थापन हेतु भारत सरकार द्वारा समर्थित 7.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण व्यवस्था (एलओसी) उपलब्ध कराने हेतु को-ऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ़ गयाना की सरकार के साथ भी करार किया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया क्रमशः यहाँ और यहाँ क्लिक करें।

VIII. आरबीआई प्रकाशन

रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर

रिज़र्व बैंक ने मार्च 2022 के महीने में अपनी वर्किंग पेपर शृंखला के तहत दो प्रकाशन प्रकाशित किए।

i) "ब्लैक स्वान से बैंकों को बचाना: ऑप्शन और ट्रेड-ऑफ" शीर्षक से पहले वर्किंग पेपर का लेखन सौरभ घोष, पवन गोपालकृष्णन और अभिषेक रंजन ने किया है। यह पेपर पूंजी लगाने की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि वह बैंकों को प्रतिकूल झटकों, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी चूक हो सकती है, के विरुद्ध एक सहारा प्रदान करता है। यह विभिन्न परिदृश्यों, जिसमें अवरुद्ध या लचीली जमा दरें शामिल हैं, के तहत पूंजी लगाने की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ii) "भारत में बैंकिंग प्रणाली का सकेन्द्रण, प्रतिस्पर्धा और सुदृढ़ता" शीर्षक से दूसरे वर्किंग पेपर का लेखन प्रदीप भुइयां ने किया है। यह पेपर 1994-95 से 2019-20 की अवधि के दौरान भारत में बैंकों का बाजार सकेन्द्रण, प्रतिस्पर्धा और सुदृढ़ता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करता है। पेपर में पाया गया है कि अध्ययन की अवधि के दौरान भारत की बैंकिंग प्रणाली को उच्च स्तरीय बाजार सकेन्द्रण द्वारा चित्रित नहीं किया गया था। यह पेपर भारत में बैंकों के लिए प्रतिस्पर्धा-स्थिरता के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा-सौम्यता दोनों के विचारों को बरकरार रखता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि अनुमानित सीमा के संबंध में कोई एक बैंक को कैसे रखा गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक समसामयिक पत्र (ऑकेजनल पेपर)

रिज़र्व बैंक ने 29 मार्च 2022 को अपने समसामयिक पत्र– खंड 42, संख्या 1, 2021 प्रकाशित किया, जिसमें निम्नलिखित लेख शामिल है;

i) *ग्रीन स्वान और भारतीय तटीय राज्यों पर उनका आर्थिक प्रभाव*

सौरभ घोष, सुजाता कुंडू और अर्चना दिलीप ने उत्पादन वृद्धि, कृषि उत्पादकता, मुद्रास्फीति, पर्यटन, राजकोषीय मापदंडों और ऋण लागत जैसे समष्टि आर्थिक संकेतकों की शृंखला पर ग्रीन स्वान घटनाओं (चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी जलवायु से संबंधित जोखिम की घटनाओं) के प्रभाव की जांच की। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ग्रीन स्वान घटनाएं मूल्य स्थिरता, संवृद्धि और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती हैं, और इस प्रकार, आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने, हरित परियोजनाओं और हरित वित्त को प्रोत्साहित करने और प्रभावी नीतिगत तैयारियों के लिए परिदृश्य विश्लेषण करने का सुझाव देती हैं।

ii) *भारत के लिए वैकल्पिक मुद्रास्फीति पूर्वानुमान मॉडल - व्यवहार में क्या बेहतर प्रदर्शन करता है?*

जिबिन जोस, हिमानी शेखर, सुजाता कुंडू, विमल किशोर और बिनोद बी. भोई ने 1996-97 की पहली तिमाही से 2019-20 की चौथी तिमाही तक भारत के तिमाही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) डेटा पर सकल और अलग-अलग स्तरों पर मुद्रास्फीति पूर्वानुमान मॉडल– स्वप्रतिगामी एकीकृत चल औसत (एआरआईएमए), संरचनात्मक सदिश स्वप्रतिगामी (एसवीएआर) और फिलिप्स कर्व (पीसी) मॉडल, का एक सूट विकसित किया है। नमूना पूर्वानुमान प्रदर्शन के आधार पर, लेखक पाते हैं कि मौसमी एआरआईएमए मॉडल एक-तिमाही आगे के होरीज़न के लिए दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि, पीसी आधारित मॉडल, भारत में मुद्रास्फीति के अलग-अलग स्तर के विश्लेषण की उपयोगिता को मान्य करते हुए, अलग-अलग स्तरों पर चार तिमाही आगे के होरीज़न में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जबकि एसवीएआर मॉडल पूर्वानुमान प्रदर्शन पर अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, वे मुद्रास्फीति पर विभिन्न झटकों के प्रभाव मूल्यांकन के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

iii) *भारत के लिए मौद्रिक स्थिति सूचकांक (एमसीआई) की दृष्टि से मौद्रिक नीति संचरण*

मनु शर्मा, अरविंद कुमार झा, अनूप के. सुरेश और बिकाश माजी ने मौद्रिक नीति संचरण के सभी चार प्रमुख चैनलों का अनुमान लगाने के लिए सामान्य अल्पकालिक ब्याज दर और विनिमय दर के अलावा, बैंक ऋण और स्टॉक की कीमतों को शामिल करके मौद्रिक स्थिति सूचकांक की पारंपरिक अवधारणा को व्यापक बनाने का प्रयास किया। उनका एमसीआई, संकट की घटनाओं सहित पिछले दो दशकों के दौरान भारत में मौद्रिक नीति के विस्तार/संकुचनात्मक चरणों को व्यापक रूप से पकड़ने की प्रवृत्ति रखता है। निर्मित एमसीआई न केवल मौद्रिक नीति के रुख का आकलन करने के लिए एक उपयुक्त संयोग संकेतक के रूप में काम करता है बल्कि मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में भी काम करता है।

iv) *उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ओटीसी व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स): वैश्विक चलनिधि और विनियामक सुधारों की भूमिका*

राजीब दास, नारायण चंद्र प्रधान और रजत मलिक ने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की चलनिधि की स्थिति के प्रभाव और चुनिंदा उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में बाजार गतिविधि पर 'ओवर-द-काउंटर' (ओटीसी) डेरिवेटिव्स पर वित्तीय क्षेत्र के विनियामक सुधारों के कार्यान्वयन की जांच की। उन्होंने पाया कि चलनिधि की अधिकता, विशेष रूप से यूएसडी चलनिधि, ने ईएमडीई के ओटीसी डेरिवेटिव्स बाजारों में ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रोत्साहन प्रदान किया; विनियामक सुधारों का ओटीसी ट्रेडिंग वॉल्यूम पर आम तौर पर अनुकूल प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स करारों पर; हालांकि सुधारों के कुछ विशेष तत्वों ने अनुपालन बोझ

बढ़ा दिया।
समसामयिक पत्र में दो पुस्तक समीक्षाएं भी शामिल हैं:
i) मधुचंदा साहू ने स्टेफ़नी केल्टन द्वारा लिखित पुस्तक द डेफिसिट मिथ: मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी एंड हाउ टू बिल्ड ए बेटर इकोनॉमी
ii) कोसुके इमाई द्वारा लिखित पुस्तक क्वांटिटेटिव सोशल साइंसेस: एन इंट्रोडक्शन। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. जारी आंकड़े

मार्च 2022 के महीने में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1)	जनवरी 2022 माह का भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
2)	जनवरी 2022 के लिए ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी संबंधी आंकड़े
3)	फरवरी 2022 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
4)	मार्च 2022 माह के लिए अनुसुचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दर
5)	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), दिसंबर 2021
6)	अक्तूबर-दिसंबर 2021 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन

X. आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2022 को अपना मासिक बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में दो भाषण, पांच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पाँच लेख निम्नानुसार हैं:

i) *अर्थव्यवस्था की स्थिति*

जारी भू-राजनैतिक संकट ने वैश्विक समष्टि-आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य पर अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, यहां तक कि विश्व अर्थव्यवस्था महामारी से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है। जैसे-जैसे संघर्ष बढ़ रहा है, वैसे-वैसे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतें कई वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच रही हैं, और बड़े पैमाने पर बिकवाली के कारण वित्तीय बाजार में घबराहट है। इस परीक्षा की अवधि में, भारतीय अर्थव्यवस्था स्पिलओवर का अनुभव कर रही है क्योंकि यह महामारी की तीसरी लहर से उबर रही है। मांग की स्थिति में सुधार के साथ-साथ उपभोक्ता और कारोबार विश्वास बढ़ रहा है। आपूर्ति पक्ष की ओर, सुदृढ़ कृषि क्षेत्र और औद्योगिक एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में निरंतर बहाली को व्यापक बना रही है।

ii) *केंद्रीय बजट 2022-23: कुछ सुखद राजकोषीय अंकगणित*

इस आलेख में केंद्रीय बजट 2022-23 का आकलन प्रस्तुत किया गया है, जो व्यावहारिक राजकोषीय शुद्धता के साथ वृद्धि पर जोर देता है।

iii) *भारतीय बैंकों के लिए हरित संक्रमण जोखिम*

इस आलेख में इस बात की जांच की गयी है कि निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की ओर संक्रमण से बैंकिंग क्षेत्र कैसे प्रभावित हो सकता है। इसमें उन उद्योगों के प्रति बैंकों के एक्सपोजर की जांच की गयी है जिन्हें इस संक्रमण और संबंधित स्पिलओवर जोखिमों के कारण उच्च समायोजन लागत का सामना करना पड़ सकता है।

iv) *एनबीएफसी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य वर्गक्रम (हाइरार्की) को डिकोड करना*

इस आलेख में एनबीएफसी के कुछ वित्तीय विवरणों की जांच की गयी है ताकि यह समझा जा सके कि आस्तियों/देयताओं को उनके उचित मूल्यों पर कैसे पहचाना, मापा और उद्घाटित किया जाता है। इस प्रक्रिया में, आलेख एक ओर विभिन्न उचित मूल्य वर्गक्रमों (हाइरार्की) के बीच सटीक अंतरों को चित्रित करने का और दूसरी ओर उनके बीच संभावित अतिव्यापन का पता लगाने का प्रयास करता है।

v) अंधानुकरण - क्या यह भारतीय शेयर बाजार में मौजूद है

इस आलेख में जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए भारतीय शेयर बाजार में अंधानुकरण का परीक्षण किया गया है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कार्य-प्रणाली, क्रॉस-सेक्शनल एब्सोल्यूट डिविएशन का उपयोग अंधानुकरण के परीक्षण के लिए किया गया है। बुलेटिन पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

XI. मौद्रिक नीति समिति की बैठक

रिज़र्व बैंक ने 30 मार्च 2022 को, 2022-23 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठकों की तारीखों की घोषणा की, जो इस प्रकार हैं:

2022-2023 के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक की समय सारणी
6 – 8 अप्रैल 2022
6 – 8 जून 2022
2 – 4 अगस्त 2022
28 – 30 सितंबर 2022
5 – 7 दिसंबर 2022
6 – 8 फरवरी 2023

स्वामित्व के बारे में विवरण और मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू से संबंधित अन्य विवरण
फॉर्म IV

प्रकाशन का स्थान	मुंबई
प्रकाशन की आवधिकता	मासिक
संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम, राष्ट्रीयता और पता	योगेश दयाल भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 400001
उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनके पास समाचार पत्र का स्वामित्व है	भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 400001

मैं, योगेश दयाल, एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

ह/-
योगेश दयाल
प्रकाशक के हस्ताक्षर
1 मार्च 2022

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।